ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-5* August- 2021
Anthology : The Research

उत्तर प्रदेश में पहचान की राजनीति और स्थानीय दल
Identity Politics and Local Parties in Uttar Pradesh

Paper Submission: 14/08/2021, Date of Acceptance: 23/08/2021, Date of Publication: 24/08/2021

अभिषेक कुमार
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ,
उत्तर प्रदेश, भारत

भारत के प्रभुत्व सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य को संविधान में ' राज्यों का संघ ' घोषित किया गया है , जिसकी दो विशेषताएं हैं : की संघात्मक व्यवस्था इकाईयों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है और इकाईयों को अपनी स्वेच्छानुसार संघ से पृथक् होने का अधिकार भी नहीं है । भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन को राज्यों की राजनीति के नाम से जाना जाता है । भारत के राज्यों के शासन के सम्बन्ध में भारतीय संघ की इकाईयों के अपने अलग संविधान नही है । यद्यपि कुछ राज्यों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान किए गए हैं , तथापि सभी राज्यों को एक जैसी शक्ति प्रदान की गई है । यह भी सत्य है कि देश के विविध राज्यों की स्थिति और सांगठनिक संरचना भिन्न - भिन्न है । राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाली भिन्न - भिन्न प्रवृत्तियों के कारण राज्य राजनीति का अध्ययन एक जटिल विषय है । राज्य राजनीति के अध्ययन को विशेष महत्व 1967 के चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात् प्राप्त हुआ है । 1967 के पश्चात् की घटनाओ के बाद विविध विद्वानों का ध्यान राज्यों की राजनीति की ओर आकर्षित हुआ ।

पहचान की राजनीति का पूरा सम्बन्ध जाति व धर्म के राजनीति से होता है । यह दुर्भाग्य की ही तो बात है , कि भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था इस प्रकार की स्थितियों का निर्धारण कर रही है और गरीब हमेशा , दलित अशिक्षित सामंतवादी उपनिवेश बने रहे । जात - पात बहुल हमारे इस समाज से यह अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है , कि समाज में व्याप्त यह भयंकर बीमारी अचानक से चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाय । इस सच्चाई को कोई कितना भी नकारे लेकिन आज भी भारतीय जनतंत्र की राजनीति के केन्द्र में नागरिक न होकर जाति ही है । देश के स्वतंत्र होने के बावजूद भी समाज से यह बीमारी दूर नहीं हो सकी है । भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को तो गैरकानूनी घोषित कर दिया , लेकिन अभी भी अस्पृश्यता समाज से मिटी नहीं। पहचान की राजनीति एक ऐसा शब्द है जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण का वर्णन करता है जिसमें किसी विशेष वर्ग के लोग है जो जाति , धर्म , लिंग , विचारधारा , राष्ट्रीयता , संस्कृति , भाषा , इतिहास , व्यवसाय या अन्य पहचान कारक राजनीतिक एजेंडा विकसित करते है और उत्पीड़न के इण्टरलॉकिंग सिस्टम के आधार पर व्यवस्थित होते है जो उनके जीवन को प्रभावित करते है और उनको पहचान मे आते है । पहचान की राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों पर हावी नहीं है बल्कि इसका असर बड़े और छोटे विश्वविद्यालयों के समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र , इतिहास इत्यादि विभागों में ऊपर से नीचे तक दिखाई देता है । स्वयंसेवी संस्थायें तो इसी से ओत - प्रोत होकर काम करती है । पहचान की राजनीति उत्तर आधुनिकवादी विचारधारा से पनपी है ।[2] शीतयुद्ध के दौरान साम्यवाद का आकर्षण इसी विचारधारा के सहारे खत्म किया गया ।[3]

The Sovereign Democratic Republic of India has been declared in the Constitution as a 'Union of States', which has two characteristics: that the federal system is not the result of agreement between the units and the units do not have the right to secede from the union at their own will. The study of the political process taking place in different states of the Indian Union is known as State Politics.In relation to the governance of the states of India, the units of the Indian Union do not have their own separate constitution. Although special provisions have been made related to some states, all the states have been given the same power. It is also true that the situation and organizational structure of different states of the country are different. The study of state politics is a complex subject due to the different trends affecting the politics of the states.The study of state politics has gained special importance after the fourth general elections of 1967. After the events of 1967, the attention of various scholars was attracted towards the politics of the states.1

The politics of identity is closely related to the politics of caste and religion. It is a matter of misfortune that the caste system is determining such conditions in Indian politics and the poor always remained dalit uneducated feudalist colonies. How can it be expected from our caste-dominated society that this dreadful disease prevailing in the society will suddenly get cured miraculously. No matter how much one denies this truth, but even today, caste is not a citizen but a citizen at the center of the politics of Indian democracy.Despite the independence of the country, this disease has not been removed from the society. The Constitution of India declared untouchability illegal, but still untouchability has not been eradicated from the society.Identity politics is a term that describes a political approach to a particular class of people who develop political agendas such as race, religion, gender, ideology, nationality, culture, language, history, occupation or other identity factor. The harassers are arranged on the basis of the interlocking systems that affect their lives and identify them Voluntary organizations work by being imbued with this. The politics of identity grew out of the postmodernist ideology.

मुख्य शब्द
जाति - पात , पहचान की राजनीति , स्थानीय दलों , अस्पृश्यता संघात्मक व्यवस्था ।
Caste-Rate, identity politics, local parties, untouchability, federal system.

प्रस्तावना

भारतीय समाज को समझने की दृष्टि उसकी राजनीति में निहित है । एक प्राचीन परम्पराबद्ध , बहुल और खंडित संरचनाओं वाला सभ्यता मूलक समाज अपनी संरचनाओं के राजनीतिकरण के माध्यम से आधुनिक बन रहा है । स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के विकास का प्रथम चरण (1947 से 1970 तक) वह है जब एक राजनीतिक केन्द्र की स्थापना करते हुए एक पार्टी के वर्चस्व वाली दलीय प्रणाली के अन्तर्गत राजनीतिक अभिजनों के सामूहिक नेतृत्व ने उपकेन्द्रों के साथ गठजोड़ निर्मित किया और उपकेन्द्र निम्न स्तर पर सक्रिय छोटे - छोटे केन्द्रों से जुडे । सरकार , राजनीतिक संस्थाओं और नियोजन के द्वारा पृथक हुए समूहों को राजनीतिक सहभागिता में खींचा गया और लोकतन्त्र का आधार विस्तृत करते हुए आर्थिक विकास करने का प्रयत्न किया गया । इस कालखण्ड में राज्य की संस्था ने समाज परिवर्तन के मुख्य कारक की भूमिका निभाई , परन्तु उसके कार्य करने का तरीका कमोवेश विकेन्द्रित रहा जो भारतीय समाज की प्रकृति के अनुकूल था । द्वितीय चरण (1971 से वर्तमान तक) वह है जब एक पार्टी के वर्चस्व वाली दलीय प्रणाली विखण्डित हो गयी और राज्य व्यवस्था जनता की मांगों को पूरा करने में असफल होने लगी , उसमें अन्तर्विरोध उत्पन्न हो गए और जनता में व्यवस्था के प्रति असंतोष में वृद्धि होने लगी । राजनीतिक सहभागिता में से व्यक्तिपरक नेतृत्व पर आधारित लोक लुभावनवादी जन राजनीति फूट पड़ी । लोकतन्त्र के नाम पर उसे सीमित करने का प्रयास किया गया , राजनीति के स्थान पर अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व प्रदान किया गया । लोकतान्त्रिक राजनीति में एक तरफ राजनीतिक सहभागिता का अधिक विकास किया , निचली जातियाँ और उपेक्षित वर्ग राजनीति की मुख्यधारा में अपनी दावेदारियां प्रस्तुत करने लगे । दूसरी ओर तकनीकशाही प्रौद्योगिकीय प्रतिमान भारतीय राज्य पर प्रभावी होते चले गए । राज्य लोकोपकार से संलग्न अपने उत्तरदायित्वों से परे जाता हुआ भूमण्डलीय अभिजनों द्वारा निर्धारित तौर - तरीके स्वीकृत करने लगा । पहचान की राजनीति ऐसी विचारधाराएँ व तर्क होते है जो किसी देश राज्य या अन्य राजनैतिक इकाई के पूर्णहित को छोड़ कर उन्न समूहो के हितों और परिप्रेक्ष्यों को बढ़ावा देने पर बल दें जिनके लोग सदस्य हों । यह समूह , जाति , धर्म , लिंग , विचारधारा , राष्ट्रीयता , संस्कृति , भाषा , इतिहास , व्यवसाय या अन्य किसी लक्षण पर आधारित हो सकते है । यह आवश्यक नही है कि जिस समूह के सन्दर्भ मे पहचान की राजनीति की जा रही है उस समूह के सभी सदस्य ऐसी राजनीतिक गतिविधियों मे भागीदार हों या उसका समर्थन करें । भारतीय छात्र संसद मे पूर्व राष्ट्रपति स्व० प्रणव मुखर्जी ने पहचान की राजनीति को लोकतंत्र के लिए अच्छा बताते हुए कहा था कि- " भारत में लोकतंत्र ने पहचान आधरित राजनीति को बढ़ावा दिया । लोकतंत्र को मजबूत करने के चश्मे से अगर मै देखू तो मुझे यह सकारात्मक बदलाव दिखता है क्योंकि इससे व्यापक प्रतिनिधित्व होता है , लेकिन जाति और समुदाय के आधार पर विभाजित मतदाता ध्रुवीकृत जनादेश देते है ।"

भारत के संविधान के अनुसार भारत मे संघीय व्यवस्था है जिसमे नई दिल्ली मे केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार है । इसीलिए , भारत में राष्ट्रीय व राज्य (क्षेत्रीय) , राजनीतिक दलों का वर्गीकरण तथा उसके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है । भारत में बहुदलीय प्रणाली अर्थात बहु - दलीय पार्टी व्यवस्था है जिसमे छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल है । राष्ट्रीय पार्टियां ये है जो चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है । उन्हे यह अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है , जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है । इस मान्यता की सहायता से राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट स्वामित्व का दावा कर सकते है ।

वे दल जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त वोट या सीटे हों , उन्हे निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रुप में अधिकृत किया जा सकता है। सम्बन्धित राज्यों में राज्य दल के रुप मे मान्यता मिलने से दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करने का विकल्प मिल सकता है । एक पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त हो सकती है , जब वह एक से अधिक राज्यों मे कुल वैध मत का 6 प्रतिशत वैध मत प्राप्त कर लेती है ।

अध्ययन का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश की पहचान आधारित राजनीतिक दलों की, राज्य की राजनीति में उद्देश्य ,भूमिका, प्रभाव, प्रासंगिकता व अन्य विविध पक्षों को रेखांकित करना।

उत्तर प्रदेश में पहचान की राजनीति का मुख्य आधार और इसके परिणाम

उत्तर प्रदेश मे आज भी साठ प्रतिशत से ऊपर जनता गरीबी के दलदल में फंसी है , देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से देश की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करने का गौरव उत्तर प्रदेश को प्राप्त है फिर भी यह राज्य आज भी पिछड़ा हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश गंगा-यमुना जैसी सदाबहार नदियों को समेटे हुए रबी , खरीफ , जायद की भरपूर मात्रा मे खाद्यान पैदा करने वाला कृषि प्रधान राज्य है । खनिज व वन सम्पदा के होते हुए भी शिक्षा , सड़क , पानी , बिजली , चिकित्सा , उद्योग धन्धे एवं रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं मे इतने पीछे होने के बाद भी इस प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व है । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति चिन्ताजनक है क्योंकि यहाँ आज भी परंपरावाद, आडम्बर , अशिक्षा अपने चरम पर है और ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकले तो पूरा प्रदेश अपराध , अव्यवस्था और भष्टाचार में जकड़ा हुआ है । कारण सिर्फ एक है क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीति का मुख्य आधार जातिवाद है प्रदेश के प्रमुख मुद्दो मे जातिवाद सर्वोपरि है , जातिवाद किसी न किसी प्रकार से हमारी राजनीति को प्रभावित करती है । हमारे समाज में एक बड़ी ही व्यापक और मुख्य भूमिका अति - पिछड़ों तथा दलितों की है , हमारे सामाजिक जीवन मे प्राचीन काल से ही दलितों की विशेष भूमिका रही है , ये समाज के ऐसे वर्ग है जिनका एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है । आज राजनीति मे या मनुष्य के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कोई कारक है तो वह जातिवाद है ।

जातियों और लोकतांत्रिक राजनीति की अन्योन्यक्रिया को आमतौर पर ' राजनीति में ' जातिवाद ' की संज्ञा दी गई है , परन्तु वास्तव में यह जातियों का राजनीतिकरण है । यह समझना आवश्यक है कि राजनीतिक संस्थाएं कहीं भी शून्य में सक्रिय नहीं रहती , उन्हें भी समाज में अपना आधार तलाशना पड़ता है । इसके लिए वे या तो मौजूदा सांगठनिक रूपों का प्रयोग करती हैं , या इन रूपों को मिला - जुला कर किसी नयी संरचना का आह्वान करती हैं और प्रकार सामाजिक आधार ग्रहण कर लेती हैं । जाति और आधुनिक संस्थाओं के मध्य हुई वास्तविक अन्योन्यक्रिया अनिवार्यतः चयनात्मक थी अर्थात् उसने जाति के कुछ पहलुओं का कुछ अन्य पहलुओं की अपेक्षा अधिक अतिक्रमण किया । उसने

सर्वप्रथम जाति प्रथा को सत्तामूलक संरचना को आधुनिकोकरण को धारा में खोंचा तत्पश्चात् आर्थिक लाभों के वितरण का समय आया , दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध था । आर्थिक लाभों के वितरण और जातिप्रथा की सत्ता सम्बन्धी संरचना में एक आंतरिक सूत्र था । इन दोनों के उत्तर प्रदेश के स्थानीय दलों को किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और जनता को भी विकास से ज्यादा अपने जाति का नेता चाहिए । कोई भी स्थानीय दल सत्ता का सोपान करने के लिए यदि आतुर होता है तो , उसे विकास न सूझ के जातिगत मुद्दा ज्यादा प्रभावशाली लगता है । ऐसी ही पहचान की राजनीति करने वाले दलों में प्रमुख है अपना दल , सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी , निषाद पार्टी , राष्ट्रीय लोक दल आदि ये दल ऐसे ही पहचान की राजनीति करते है और अपने - अपने जातियों समुदायों का शासन सत्ता में भागीदारी चाहते है ।

उत्तर प्रदेश में पहचान की राजनीति करने वाले प्रमुख स्थानीय दलों का उदय तथा प्रसार

लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है । इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं । भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है । लेकिन , हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता ।

अपना दल

जिसकी स्थापना 4 नवम्बर 1994 को डॉ ० सोनेलाल पटेल ने इन्जिनियर बलिहारी पटेल के साथ मिलकर किया । डॉ सोनेलाल पटेल पूर्व मे बहुजन समाज पार्टी में थे । कांशीराम से मतभेद के चलते उन्होंने समाज के दबे कुचले कमजोरों और पिछड़ों को लेकर अपना दल की नींव रखी । अपना दल के गटन से पूर्व उन्होंने लखनऊ के वेगम हजरत महल पार्क में एक कुर्मी , क्षत्रीय महारैली का आयोजन किया , जिसमें अपार जनता की भीड़ उपस्थित हुई । इस रैली को बी बी सी न्यूज ने सबसे बड़ी जातीय रैली बताया । उनके साथ लोग जुड़ते गये और अपना दल को जनाधार मिल गया । अक्टूबर 2009 मे एक सड़क दुर्घटना मे डॉ सोनेलाल पटेल के निधन के बाद अपना दल दो भागों मे बट गया , एक पत्नी कृष्णा पटेल व दूसरी बेटी अनुप्रिया पटेल का ।[6]

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी

जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के भर यानि राजभर जाति की राजनीतिक आकांक्षाओ को आगे बढ़ाने खयाल से ओम प्रकाश राजभर ने 2002 में की । पार्टी के घड़ी पुनाव चिन्ह तथा पीले ध्वज के साथ त्य नेतृत्व भी ओमप्रकाश राजभर ही करते है । 2014 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार श्री नरेन्द्र मोदी जी को वाराणसी लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का जब निर्णय लिया और श्री मोदी जी का जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी समुदायों कों साधने की नीति के तहत अपना दल के साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे छोटे दलों से भी चुनावी ताल मेल के दिशा में काम किया । सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2014 के चुनाव में अपने 13 उम्मीदवार उतारने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एकता मंच के बैनर तले छोटे दलों का एक सियासी गुलदस्ता तैयार किया और एन0 डी0 ए0 की मदद की । 2014 के लोक सभा चुनाव में भले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी उमीदवारों की जमानत जब्त हो गयी लेकिन इसका लाभ 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला और इनके 4 प्रत्याशी चुनाव मे सफल हुए तथा ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बन गये । आरक्षण का लाभ न लेने वाली पिछडे वर्ग के अलग आरक्षण का लाभ दिलवाने हेतु सरकार से विवाद कर वे एन0 डी0 ए0 से अलग हो गये तथा अपने मंत्री पद को त्याग दिया ।[7]

निषाद पार्टी

निषाद पार्टी की स्थापना निषाद जाति के सशक्तिकरण के लिए 2016 में हुई । निषादपार्टी के संस्थापक बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सदस्य संजय निषाद है । निषाद पार्टी का अर्थ " निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल " है । निषाद पार्टी का गठन निषाद , केवट , विन्द और अन्य समुदायों के सशक्तिकरण के लिए किया गया था जिनका पारम्परिक व्यवसाय नदियों पर केन्द्रित था । श्री निषाद के अनुसार इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अलग पार्टी की आवश्यकता थी क्योंकि उन्होनें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जीत मे अभिन्न भूमिका निभाई थी । समाजवादी पार्टी ने 2018 में फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा उपचुनावों के लिए यादवों और मुसलमानों से परे अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने के लिए निषाद पार्टी सहित कई छोटे दलो के साथ गठबंधन किया । लोक सभा उप चुनाव मे समाजवादी पार्टी से गठबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किले को फतह करने में निषाद पार्टी सफल रही । 1989 के याद एक भी सीट न हारने वाली भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा । 2019 मे निषाद पार्टी राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन मे शामिल हो गयी जिसमे प्रवीण कुमार निषाद भारतीय जनता पार्टी के टीकट पर संत कबीर नगर निर्वाचन क्षेत्र से लड़े और चुने गये ।[8]

राष्ट्रीय लोक दल

राष्ट्रीय लोक दल का आरम्भ चौधरी चरण सिंह के भारतीय लोक दल से माना जा सकता है 1974 मे स्थापित इस दल का चुनाव निशान हलधर किसान हुआ करता था । सन् 1977 ई ० मे इन्दिरा गाँधी को हराने के लिए कई दलों के विलय के बाद भारतीय लोक दल का पुनरोदय हलधर किसान पुनाव चिन्ह के साथ जनता पार्टी के रुप मे हुआ । जनता पार्टी के उदय का उद्देश्य श्रीमती इन्दिरा गाँधी को 1977 के चुनाव मे हरा के पूरा हो चुका था मोरार जी देशाई के बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी के तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री हुए । यह जनता पार्टी मात्र तीन वर्षो मे टूट गयी और चौधरी चरण सिंह ने फिर एक नया दल का गठन किया जिसको लोक दल के नाम से हम जानते है जिसका चुनाव चिन्ह था हल जोतता हुआ किसान । ये दल 1987 मे चौधरी चरण सिंह के देहांत तक चला । उस समय नीतिश कुमार , देवी लाल , बीजू पटनायक , मुलायम सिंह और शरद यादव जैसे दिग्गज नेताओं की पहचान लोक दल से हुआ करती थी । लेकिन चौधरी चरण सिंह के दिवंगत होने के बाद एक बार फिर लोक दल पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गयी । कुछ दिनो हेमवती नंदन बहुगुणा इसके अध्यक्ष रहे किन्तु फिर भी यह लड़ाई निर्वाचन आयोग तक पहुँच गयी क्योंकि इस बार चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह भी पार्टी पर अपना दावा ठोक रहे थे । चुनाव आयोग ने यह कहते हुए उनका दावा ठुकरा दिया कि पिता के सम्पत्ति का वारिस उनका बेटा हो सकता है लेकिन पार्टी की विरासत उसे नही मिल सकती । इसके बाद अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई ।[9]

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज जातिगत भेद - भाव से इस कदर भरा पड़ा है , जो भयानक बीमारियों की तरह हमारे समाज को जकड़े हुए है , इसका निदान खोज पाना

कांठेन मालूम पड़ता है । यह केवल व्यक्ति - व्यक्ति के बीच खाई पैदा नहीं कर रही , बल्कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा पहुंचाने का कार्य कर रही है । प्रत्येक राज्य में दलित अल्पसंख्यक हैं , जो विभिन्न जातियों के साथ मिश्रित जनसंख्या वाले समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं । इसका अर्थ यह है , कि चुनाव के समय वे उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं , संघ के सभी राज्यों मे और हर राज्य के प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच उनका वोट है इसलिए राजनीतिक दलों को अधिकांश लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दलित हितों का ध्यान रखना पड़ता है । दलित मतदाता लगभग 300 निर्वाचन क्षेत्रों के निर्णय में असरदार भूमिका निभाते हैं । पहचान की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान जाति प्रथा के कारण समाज टुकड़ों में बंट गया , व्यक्ति - व्यक्ति के बीच भेदभाव गया , अहंकार और द्वेष के फलस्वरूप प्रदेश की एकता अखण्डता प्रभावित हो रही है ।

वैसे तो संविधान द्वारा अस्पृश्यता को लेकर अनेक कानून बनाए गए , परन्तु जाति - विहीन समाज की स्थापना संविधान की अंतरात्मा नहीं बन पाई । अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई परन्तु जाति व्यवस्था स्वयं बनी रही । अनुच्छेद 17 का अंबेडकर द्वारा किया गया प्रारूप यह था कि रैंक , जन्म , व्यक्ति , परिवार , धर्म या धार्मिक रुढ़ि और रीति - रिवाज से उत्पन्न किसी विशेषाधिकार या निर्योग्यता को समाप्त किया जाता है , परंतु इसे न तो प्रारूप समिति ने स्वीकार किया और न ही संविधान सभा ने स्वीकार किया । बिना चतुर या जाति नाम लिए अंबेडकर ने इन पर आधारित विशेषाधिकारों या निर्योग्यताओं को समाप्त करने का प्रयास किया था और यदि उसे स्वीकार किया गया होता तो यह सामाजिक समता तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा के ज्यादा समीप होता । प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्रीनिवास का मत है कि " परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है , कि ये राजनीतिक संस्थाएँ अपने मूलरूप में कार्य करने में समर्थ नहीं है । " अतः जातिवाद देश समाज और राजनीति के लिए बाधक सिद्ध प्रतीत होती है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Manisha Sharma.pdf (uok.ac.in)*
2. *Manisha Sharma.pdf (uok.ac.in)*
3. *Identity Politics Is Big Challenge – चनौतीहैपहचानकीराजनीति*
4. *-Amar Ujala Hindi News Live*
5. *पहचानआधारितराजनीतिलोकतंत्रकेलिएअच्छीहै : मुखर्जी - Identity based politics is good for democracy former president pranab mulherjee - Latest News & Updates in Hindi at India.com Hindi*
6. *डॉ ० कोठारी , रजनी - भारत में राजनीति : कल और आज , वाणी प्रकाशन , दिल्ली 2006 , पृ 0251*
7. *अपनादल-विकिपीडिया(wikipedia.org)*
8. *सुहेलदेवभारतीयसमाजपार्टी-विकिपीडिया(wikipedia.org) निषादपार्टीइतिहासदेखेंअर्थऔरसामग्री - hmoob.in*
9. *लोकदल - विकिपीडिया (wikipedia.org)*